

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 623वीं बैठक दिनांक 21/02/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
6. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No 8384/2021 Shri Rasmeet Singh Malhotra, Project Proponent, R/o Nehru Ward No. 13, Near Alka Talkies, Pipariya, District-Hoshangabad (MP)-461775, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 15.0 ha. (1,62,000 cum per annum) (Khasra No. 263/1, 263/2), Village - Ajanda-2, Tehsil - Gadarwara, Dist. Narsinghpur (MP).**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 263/1, 263/2), Village - Ajanda-2, Tehsil - Gadarwara, Dist. Narsinghpur (MP).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 493वीं दिनांक 23/03/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अभिषेक निगम और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार डॉ जतिन श्रीवास्तव, मेसर्स पी एंड एम सल्यूशन, नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान दूधी नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-78 के सरल क्रमांक-2.9 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल-3,78,000 मैट्रिक टन (2,70,000 घनमीटर) उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1,62,000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

हेतु आवेदन किया गया था, जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) से कम है। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्षेत्र व गहराई के आधार पर इस खदान का माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)–2,70,000 घनमीटर हैं तथा अनुमोदित माइन प्लॉन के अनुसार केवल रेत प्राप्ति की मात्रा 1,62,000 घनमीटर दर्शाई गई है, जो उपलब्ध मात्रा से काफी कम है। अतः खनिज विभाग यह सुनिश्चित करें कि स्वीकृत मात्रा 1,62,000 घनमीटर/वर्ष से अधिक का उत्पादन इस खदान से न हो, जिस हेतु मॉनिटरिंग संबंधी विशेष व्यवस्थाएँ स्थापित की जाये।

स्वीकृत लीज की समयावधि एक वर्ष से भी कम (जून, 2023 तक) ही है। समिति की यह चिंता है कि इतनी कम अवधि होने के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा ग्राम में पौधारोपण, स्कूल की बिल्डिंग मरम्मत, पीने के पानी की व्यवस्था, गांव के मंदिर में कार्य, समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर इत्यादि के सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 1,62,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 38.25 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 02.33 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति- कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा, डेंचा एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	15000
2	परिवहनमार्ग (1 मीटर ऊंचाई के पौधे)	खमेर, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
3	आवंटित क्षेत्र के आस पास के ग्राम में तथा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, बेर, आँवला, सीताफल, नींबू, बेल, एवं अन्य स्थानीय फलदार पौधों की प्रजातियाँ	2800
योग			18,000

- सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

S. NO.	DEVELOPMENT INDICATORS	COST ALOTTED
1.	Repairing of the school building along with installation of Hand Pump for drinking water in the school building (as per public hearing)	2,50,000/-
2.	Construction of Pukka chabutra (size 5' x 8') in nearby worship place of village Ajanda (as per the discussion of public hearing)	50,000/-
3.	Repairing of the Road (pot holes) at the Village PMSY road	1,50,000/-
4.	Medical Health Check-up (through PHC) drive with the distribution of medicines	50,000/-
5.	For maintenance of Nauradehi WLS and welfare of staff	100,000/-
	TOTAL	Rs.5,00,000/-

- Case No 7918/2020 M/s. Euphoria Mines and Minerals, Partner, Shri Himanshu Meena, R/o 9 A, Paramount Villa, Ansals, Shyamla Hills, District-Bhopal (MP)-462013 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 6.0 ha. (30,000 cum per annum) (Khasra No. 574), Village - Tila-2, Tehsil - Naugaon, Dist. Chhatarpur (MP). (EIA).**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. - 572), Village - Tila, Tehsil - Naugaon, Dist. Chhatarpur (MP). (EIA).

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 668 वीं दिनांक 16/12/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु मीणा (ऑनलाईन) एवं उनके पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान धसान नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज (जनवरी, 2022) अनुसार अनुसार खदान पूर्णतः जलमग्न है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि फरवरी-मार्च के बाद नदी का यह पानी सूख जाता है तथा उसके पश्चात् खनन कार्य किया जा सकता है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यदि पुरानी गूगल इमेज जनवरी, 2021 का अवलोकन करें पायेंगे कि खदान प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने यह भी स्पष्ट किया कि आवंटित खनन क्षेत्र का उत्तरी भाग जहाँ से नदी का प्रवाह है, वहाँ खनन कार्य नहीं किया जायेगा तथा उसे नॉन माइनिंग जोन घोषित किया गया है तथा उसे पुनरीक्षित सरफेस मैप में प्रस्तुतीकरण के साथ दिखाया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा इस संबंध में संबंधित खनिज अधिकारी से भी जानकारी प्राप्त की गई है तथा संबंधित खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 406 दिनांक 21/02/23 के माध्यम से अवगत कराया है कि स्वीकृत रेत खदान में अप्रैल से मई माह तक जल भराव कम हो जाता है, जिससे खदान में उत्खनन कार्य किया जा सकता है, जिसकी प्रति प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न की गई है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित कुल 06.00 क्षेत्र में से खनन योग्य क्षेत्र 03.60 हे. है।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-77 के सरल क्रमांक-38 पर इस खदान का विवरण दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-1,08,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति चाही गई है, जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) से कम है। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्षेत्र व गहराई के आधार पर इस खदान का माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-1,08,000 घनमीटर हैं तथा अनुमोदित माइन प्लॉन के अनुसार केवल रेत प्राप्ति की मात्रा 30,000 घनमीटर दर्शाई गई है, जो उपलब्ध मात्रा से काफी कम है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन के पूर्व इस जिले का टेंडर संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो गई थी, जिस कारण मात्रा में अंतर आ रहा है। समिति की अनुशंसा है कि इस स्थिति में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दी गई मात्रा का पुनः निर्धारण जिला खनिज अधिकारी द्वारा किया जाना उचित होगा। इसी प्रकार खनिज विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत मात्रा

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

30,000 घनमीटर/वर्ष से अधिक का उत्पादन इस खदान से न हो, जिस हेतु मॉनिटरिंग संबंधी विशेष व्यवस्थाएँ स्थापित की जाये ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत लीज की समयावधि एक वर्ष से भी कम (जून, 2023 तक) ही है । समिति की यह चिंता है कि इतनी कम अवधि होने के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 032 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा ग्राम में रेत का परिवहन मार्ग की सड़कों पर जल का छिड़काव, वाहनों की गति का नियंत्रित परिचालन इत्यादि हेतु सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 30,000 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 17.72 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 04.16 लाख प्रति वर्ष ।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 09.22 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयं वृक्षों की प्रजातियाँ चयनित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।
5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति— खस, नागर मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति— कटंग बांस 6 पंक्ति — करंज, जामुन, लसोड़ा, डेंचा एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	6150
2	टीला के प्राथमिक विद्यालय में वितरण हेतु	कदम्ब, अमलतास, पुत्ररंजीवा, अशोक, नीम, कनक-चंपा, मौलश्री, परीजात गुलमोहर इत्यादि।	50
3	ग्राम टीला के ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, बेर, आँवला, सीताफल, नींबू, बेल, एवं अन्य स्थानीय फलदार पौधों की प्रजातियाँ	1000
योग			7200

6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
क्रोकोडाइल घड़ियाल सैंक्चुअरी, छतरपुर, उनके रहवास व कर्मचारी कल्याण हेतु पन्ना टाइगर रिजर्व को धनराशि दी जाएगी।	1,00,000 /—

3. Case No 7899/2020 M/s Pushpa Enterprises, Prop. Shri Anand Tamrakar, G-7, 8, Deendayal Parisar, E-2, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 14.0 ha. (1,00,000 cum per annum) (Khasra No. 697/1), Village - Nehra, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP). (EIA).

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. - 697/1), Village - Nehra, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 476 वीं दिनांक 02/12/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद ताम्रकार (ऑनलाईन), एवं पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान केन नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान का कुछ भाग (उत्तरी) नदी के जल में डूबा है, जिसके संदर्भ परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस भाग से रेत निकाले जाने के कारण ऐसा दिख रहा है तथा नदी का वह भाग जिसमें पानी भरा हुआ है, वहाँ पर खनन प्रस्तावित नहीं है तथा उसे नॉन माइनिंग जोन घोषित किया गया है तथा उसे पुनरीक्षित सरफेस मैप में प्रस्तुतीकरण के साथ दिखाया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित कुल 14.00 क्षेत्र में से खनन योग्य क्षेत्र 06.50 हे. है तथा रेत का परिवहन उत्तरी दिशा से किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-75 के सरल क्रमांक-21 पर इस खदान का विवरण दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-2,52,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1,00,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति चाही गई है, जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) से कम है। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्षेत्र व गहराई के आधार पर इस खदान का माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-2,52,000 घनमीटर हैं तथा अनुमोदित माइन प्लॉन के अनुसार केवल रेत प्राप्ति की मात्रा 1,00,000 घनमीटर दर्शाई गई है, जो उपलब्ध मात्रा से काफी कम है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन के पूर्व इस जिले का टेंडर संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो गई थी, जिस कारण मात्रा में अंतर आ रहा है। समिति की अनुशंसा है कि इस स्थिति में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दी गई मात्रा का पुनः निर्धारण जिला खनिज अधिकारी द्वारा किया जाना उचित होगा। इसी प्रकार खनिज विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत मात्रा 1,00,000 घनमीटर/वर्ष से अधिक का उत्पादन इस खदान से न हो, जिस हेतु मॉनिटरिंग संबंधी विशेष व्यवस्थायें स्थापित की जाये।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत लीज की समयावधि एक वर्ष से भी कम (जून, 2023 तक) ही है। समिति की यह चिंता है कि इतनी कम अवधि होने के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा ग्राम में पेयजल की व्यवस्था (हेण्डपंप), रोजगार, खेतों से रेत को नही निकाला जायेगा, स्कूल में कम्प्यूटर एवं नदी में बाढ़ आने पर रास्ता दिया जावेगा इत्यादि हेतु सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी.

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

/सी.ई.आर. में शामिल किया गया। खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 1,00,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 31.24 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 04.35 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 23.62 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयं वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति- कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा, डेंचा एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	15750
2	ग्राम नेहरा, के प्राथमिक विद्यालय में वितरण हेतु।	कदम्ब, अमलतास, पुत्ररंजीवा, अशोक, नीम, कनक-चंपा, मौलश्री, परीजात गुलमोहर इत्यादि।	50
3	नेहरा, के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, बेर, आँवला, सीताफल, नींबू, बेल, एवं अन्य स्थानीय फलदार पौधों की प्रजातियाँ	1000
योग			16,800

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम नेहरा में पानी के लिए एक हैंड पंप के साथ रिचार्जिंग पिट लगाए जाएंगे	50,000 /—
ग्राम नेहरा के शासकीय स्कूल में एक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर	50,000 /—
क्रोकोडाइल घड़ियाल सैंक्चुअरी, छतरपुर, उनके रहवास व कर्मचारी कल्याण हेतु पन्ना टाइगर रिजर्व को धनराशि दी जाएगी।	50,000 /—
योग	1,50,000 /—

4. **Case No 9586/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Astot Sand Quarry in an area of 4.80 ha. (13,110 cum per annum) (Khasra No. 587, 646, 654), Village-Astot, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP).**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 587, 646, 654), Village-Astot, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) 4.80 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 08 दिनांक 02/01/2023 (लीज हस्तांतरित) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश-देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश-देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को-आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को-आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा है / आवंटित खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश त्रुटिपूर्ण है।

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

समिति ने पाया कि आज दिनांक 21/02/23 को दतिया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरू खनन् का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता। अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन् क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये। समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये।

5. Case No 9579/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP) - 477660, Prior Environment Clearance for Kanjoli-2 Sand Quarry in an area of 4.90 ha. (5,130 cum per annum) (Khasra No. 01), Village-Kanjoli-2, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01), Village-Kanjoli-2, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP) 4.90 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 31 दिनांक 02/01/2023 (लीज हस्तांतरित) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश-देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश-देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को-आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन् क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को-आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा है / आवंटित खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलान नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि आज दिनांक 21/02/23 को दतिया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 फरवरी 2023

स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरू खनन् का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता । अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन् क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये । समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये ।

6. Case No 9585/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Ajeetpura Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (7920 cum per annum) (Khasra No. 01), Village-Ajeetpura, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01), Village - Ajeetpura, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) 3.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 24 दिनांक 02/01/2023 (खदान हस्तांतरित) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश-देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश-देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को-आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन् क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को-आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा है / आवंटित खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश त्रुटिपूर्ण है ।

समिति ने पाया कि आज दिनांक 21/02/23 को दतिया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरू खनन् का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता । अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन् क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 फरवरी 2023

प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये । समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये ।

7. Case No 9591/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Mustara Sand Quarry in an area of 4.740 ha. (9,900 cum per annum) (Khasra No. 503, 596), Village-Mustara, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 503, 596), Village-Mustara, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) 4.740 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 09 दिनांक 02/01/2023 (लीज हस्तांतरित) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश-देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश-देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को-आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को-आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा है / आवंटित खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता । इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश त्रुटिपूर्ण है ।

समिति ने पाया कि आज दिनांक 21/02/23 को दतिया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरु खनन का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता । अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये । समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 फरवरी 2023

रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये ।

8. Case No 9593/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Basaimalak-2 Sand Quarry in an area of 4.980 ha. (11,970 cum per annum) (Khasra No. 292, 295, 296), Village-Basaimalak-2, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP).

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 292, 295, 296), Village-Basaimalak-2, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP) 4.980 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 26 दिनांक 02/01/2023 (लीज हस्तांतरित) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश-देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश-देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को-आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को-आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा है / आवंटित खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश त्रुटिपूर्ण है ।

समिति ने पाया कि आज दिनांक 21/02/23 को दतिया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरू खनन का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता । अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये । समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये ।

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 फरवरी 2023

9. Case No 9594/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Madikheda Sand Quarry in an area of 4.900 ha. (23,393 cum per annum) (Khasra No. - 01), Village-Basaimalak-2, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01), Village-Basaimalak-2, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP) 4.900 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 28 दिनांक 02/01/2023 (लीज हस्तांतरित) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश-देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश-देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को-आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को-आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा है / आवंटित खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि आज दिनांक 21/02/23 को दतिया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरू खनन का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता। अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये। समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये।

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 फरवरी 2023

10. Case No 9595/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Marseni Khurd Sand Quarry in an area of 4.800 ha. (14,962.5 cum per annum) (Khasra No. 01), Village-Marseni, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01), Village-Marseni, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP) 4.800 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 27 दिनांक 02/01/2023 (लीज हस्तांतरित) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश-देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश-देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को-आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को-आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा है / आवंटित खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि आज दिनांक 21/02/23 को दतिया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरू खनन का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता। अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये। समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये।

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 फरवरी 2023

11. Case No 9596/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Saletara Sand Quarry in an area of 4.840 ha. (14,940 cum per annum) (Khasra No. 814), Village-Saletara, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. - 814), Village-Saletara, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) 4.840 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 10 दिनांक 02/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश-देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश-देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को-आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को-आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा है / आवंटित खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि आज दिनांक 21/02/23 को दतिया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरू खनन का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता। अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये। समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये।

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 फरवरी 2023

12. Case No 9597/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Kutauli Sand Quarry in an area of 4.600 ha. (27,740 cum per annum) (Khasra No. 1/1), Village-Kutauli, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1/1), Village-Kutauli, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) 4.600 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 22 दिनांक 02/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश-देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश-देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को-आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को-आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा है / आवंटित खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि आज दिनांक 21/02/23 को दतिया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरु खनन का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता। अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये। समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये।

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 फरवरी 2023

13. Case No 9598/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Kanjoli-1 Sand Quarry in an area of 3.460 ha. (3,990 cum per annum) (Khasra No. 138), Village-Kanjoli-1, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. - 138), Village-Kanjoli-1, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP) 3.460 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 16 दिनांक 02/01/2023 (लीज हस्तांतरित) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश-देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश-देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को-आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को-आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा है / आवंटित खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि आज दिनांक 21/02/23 को दतिया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरू खनन का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता। अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये। समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये।

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 फरवरी 2023

14. Case No 9600/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Ruhera Sand Quarry in an area of 4.600 ha. (9,975 cum per annum) (Khasra No. 765, 2222), Village-Ruhera, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 765, 2222), Village-Ruhera, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP) 4.600 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 29 दिनांक 02/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश-देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश-देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को-आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को-आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा है / आवंटित खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि आज दिनांक 21/02/23 को दतिया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरू खनन का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता। अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये। समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये।

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 फरवरी 2023

15. Case No 9602/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Dhamna Sand Quarry in an area of 4.60 ha. (9,900 cum per annum) (Khasra No. 935), Village-Dhamna, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 935), Village-Dhamna, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) 4.900 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 29 दिनांक 02/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश-देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश-देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को-आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को-आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा है / आवंटित खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि आज दिनांक 21/02/23 को दतिया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरु खनन का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता। अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये। समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये।

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 फरवरी 2023

16. Case No 9631/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Ajeetpura-2 Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (17,955 cum per annum) (Khasra No. 514), Village-Ajeetpura-2, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP).

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 514), Village-Ajeetpura-2, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP). 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 23 दिनांक 02/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश-देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश-देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को-आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को-आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा है / आवंटित खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि आज दिनांक 21/02/23 को दतिया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरू खनन का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता। अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये। समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये।

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 फरवरी 2023

17. Case No 9624/2023 Shri Rasmeet Singh Malhotra, Owner R/o Nehru Ward No. 13, Near Alka Talkies, Pipariya, District-Hoshangabad (MP)-461775, Prior Environment Clearance for Kihiriya Sand Quarry (Shakkar River) in an area of 4.00 ha. (64,800 Cum per annum) (Khasra No. 21/1K), Village- Khiriya, Tehsil-Gadarwara, District-Narsinghpur (MP).

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 21/1K), Village- Khiriya, Tehsil-Saikheda, District-Narsinghpur (MP). Lease Area – 4.00 Ha., The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 22/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रसमीत मल्होत्रा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अभिषेक निगम एवं पर्यावरण सलाहकार श्री किशन शर्मा, मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एवं इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंटरनेशनल, जयपुर उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 941 दिनांक 10/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान शक्कर नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-79 के सरल क्रमांक-4. 2 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-1,00,800 मैट्रिक टन (72,000 घनमी.) उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 64,800 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 64,800 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.37 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 02.51 लाख प्रति वर्ष।

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 6.02 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।
5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति- कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा, डेंचा एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	2500
2	परिवहन मार्ग (पौधों की ऊंचाई 1 मीटर)	खमेर, चिरोल, साजा, सप्तपर्णी, अचार, करंज, जंगल जलेबी, कदम, एवं अन्य प्रजातियाँ	750
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत खिरिया)	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, सीताफल, नींबू, अचार, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1550
कुल			4800

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम खिरिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1-स्ट्रेचर बेड एवं सामान्य जरूरी चिकित्सीय उपकरण जैसे शुगर, बीपी, वजन नापने की मशीन की व्यवस्था ।	25000
तहसील साईखेड़ा के समुदायिक चिकित्सा केंद्र ECG मशीन एवं 1 स्ट्रेचर बेड की	1,00,000

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 फरवरी 2023

व्यवस्था।	
कुल योग	1,25,000

18. Case No 9625/2023 Shri Rasmeet Singh Malhotra, Owner, R/o Nehru Ward No. 13, Near Alka Talkies, Pipariya, District-Hoshangabad (MP)-461775, Prior Environment Clearance for Hirapur Sand Quarry (Narmada River Sand) in an area of 5.00 ha. (81,000 Cum per annum) (Khasra No. 605), Village-Hirapur, Tehsil-Thendukheda, District-Narsinghpur (MP) .

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 605), Village-Hirapur, Tehsil-Thendukheda, District-Narsinghpur (MP) Lease Area – 5.00 Ha., The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 22/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रसमीत मल्होत्रा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अभिषेक निगम एवं पर्यावरण सलाहकार श्री किशन शर्मा, मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एवं इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंटरनेशनल, जयपुर उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 885 दिनांक 10/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान नर्मदा नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। चूंकि खदान नर्मदा नदी में स्थित है अतः सिर्फ मेनुअल माईनिंग की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-77 के सरल क्रमांक-1.10 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-1,26,000 मैट्रिक टन (90,000 घनमीटर/वर्ष) उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 81,000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। अतः पर्यावरणीय अभिस्वीकृति इसी मात्रा अर्थात् 81,000 घनमीटर/वर्ष हेतु अनुशंसित किया जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 81,000 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.34 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 02.83 लाख प्रति वर्ष ।
3. प्रस्तावित खनन कार्य नर्मदा नदी पर होने के कारण मेन्यूअल माईनिंग संचालित की जावेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 07.90 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयनित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।
6. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति- कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा, डेंचा एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	3600
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत हीरापुर)	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, सीताफल,, नींबू, अचार, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1800
2	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, साजा, सप्तपर्णी, अचार, करंज, जंगल जलेबी, कदम, एवं अन्य प्रजातियाँ	600
कुल			6000

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

7. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
तहसील तेंदूखेड़ा के शासकीय चिकित्सालय में दो स्ट्रेचर बेड एवं दो व्हीलचेयर की व्यवस्था	50,000
नौरादेही अभ्यारण में वन्य प्राणियों के रहवास, संरक्षण एवं कर्मचारी कल्याण हेतु	50,000
कुल योग	1,00,000

19. Case No 9626/2023 Shri Rasmeet Singh Malhotra, Owner, R/o Nehru Ward No. 13, Near Alka Talkies, Pipariya, District-Hoshangabad (MP)-461775, Prior Environment Clearance for Bhumiyaadana Sand Quarry in an area of 4.98 ha. (80,676 Cum per annum) (Khasra No. 01), Village-Bhumiyaadhana, Tehsil-Gadarwara, District-Narsinghpur (MP).

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01), Village-Bhumiyaadhana, Tehsil-Gadarwara, District-Narsinghpur (MP). Lease Area – 4.98.00 Ha., The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 22/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रसमीत मल्होत्रा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अभिषेक निगम एवं पर्यावरण सलाहकार श्री किशन शर्मा, मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एवं इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंटरनेशनल, जयपुर उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 901 दिनांक 10/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान नर्मदा नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। चूंकि खदान नर्मदा नदी में स्थित है अतः सिर्फ मेनुअल माईनिंग की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-77 के सरल क्रमांक-1.2 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-1,25,496 मैट्रिक टन (89,640 घनमीटर/वर्ष) उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 80,876 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। अतः पर्यावरणीय अभिस्वीकृति इसी मात्रा अर्थात् 80,676 घनमीटर/वर्ष हेतु अनुशंसित किया जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

पौधों की देख-भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत — 80,676 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.44 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.85 लाख प्रति वर्ष।
3. प्रस्तावित खनन कार्य नर्मदा नदी पर होने के कारण मेन्यूअल माईनिंग संचालित की जावेगी।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
5. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 8.00 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
6. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति- कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा, डेंचा एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	3400
2	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, साजा, सप्तपर्णी, अचार, करंज, जंगल जलेबी, कदम, एवं अन्य प्रजातियाँ	800

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 फरवरी 2023

2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत भूमियादानी)	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, सीताफल, नींबू, अचार, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1800
कुल			6000

7. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
प्राथमिक विद्यालय भूमियादानी के तीन कमरों के फर्श का निर्माण, विद्यालय की रंगाई पुताई,	50,000
नौरादेही अभ्यारण में वन्य प्राणियों के रहवास, संरक्षण एवं कर्मचारी कल्याण हेतु	50,000
कुल योग	1,00,000

20. Case No 9627/2023 Shri Rasmeet Singh Malhotra, Owner, R/o Nehru Ward No. 13, Near Alka Talkies, Pipariya, District-Hoshangabad (MP)-461775, Prior Environment Clearance for Rewanagar Sand Quarry (Narmada Sand) in an area of 3.466 ha. (56,148 Cum per annum) (Khasra No. 20/1), Village-Rewanagar, Tehsil-Kareli, District-Narsinghpur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (56,148 Cum per annum) (Khasra No. 20/1), Village-Rewanagar, Tehsil-Kareli, District-Narsinghpur (MP) Lease Area – 3.466 Ha., The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 22/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रसमीत मल्होत्रा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अभिषेक निगम एवं पर्यावरण सलाहकार श्री किशन शर्मा, मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एवं इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंटरनेशनल, जयपुर उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 897 दिनांक 10/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान नर्मदा नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। चूंकि खदान नर्मदा नदी में स्थित है अतः सिर्फ मेनुअल माईनिंग की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-77 के सरल क्रमांक-1.4 पर दर्ज है, जिसमें

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-87,343.20 मैट्रिक टन (62,387 घनमीटर/वर्ष) उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 56,148 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। अतः पर्यावरणीय अभिस्वीकृति इसी मात्रा अर्थात् 56,148 घनमीटर/वर्ष हेतु अनुशंसित किया जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेट – 56,148 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 11.93 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.68 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रूपये 05.33 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति- कटंग बांस	2500

**622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 फरवरी 2023**

		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा, डेंचा एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	
2	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, साजा, सप्तपर्णी, अचार, करंज, जंगल जलेबी, कदम, एवं अन्य प्रजातियां	500
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत रेवनगर)	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, सीताफल, नींबू, अचार, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1160
कुल			4160

6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम रेवनगर प्राथमिक शाला में 20 बेंच एवं 2 ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था एवं बच्चों के खेलने हेतु खेलकूद की सामग्री का वितरण एवं प्राथमिक शाला में पुताई का कार्य	50,000
नौरादेही अभ्यारण में वन्य प्राणियों के रहवास, संरक्षण एवं कर्मचारी कल्याण हेतु	50,000
कुल योग	1,00,000

21. Case No 9639/2023 Shri Rasmeet Singh Malhotra, Owner, R/o Nehru Ward No. 13, Near Alka Talkies, Pipariya, District-Hoshangabad (MP)-461775, Prior Environment Clearance for Bairagarh Sand Quarry (On Dudhi River) in an area of 4.80 ha. (77,760 Cum per annum) (Khasra No. 176), Village-Bairagarh, Tehsil-Gadarwara, District-Narsinghpur (MP).

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (77,760 Cum per annum) (Khasra No. 176), Village-Bairagarh, Tehsil-Gadarwara, District-Narsinghpur (MP). Lease Area – 4.80 Ha., The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 22/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रसमीत मल्होत्रा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अभिषेक निगम एवं पर्यावरण सलाहकार श्री किशन शर्मा, मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एवं इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंटरनेशनल, जयपुर उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 903 दिनांक 10/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान दूधी नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-78 के सरल क्रमांक-2.16 पर इस खदान का विवरण दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-1,20,960 मैट्रिक टन (86,400 घनमीटर/वर्ष) उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 77,760 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति चाही गई है। अतः पर्यावरणीय अभिस्वीकृति इसी मात्रा अर्थात् 77,760 घनमीटर/वर्ष हेतु अनुशंसित किया जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 77,760 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 13.34 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 02.64 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 07.62 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयं वृक्षों की प्रजातियाँ चयनित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

**622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 फरवरी 2023**

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति- कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा, डेंचा एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	3200
2	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, साजा, सप्तपर्णी, अचार, करंज, जंगल जलेबी, कदम, एवं अन्य प्रजातियाँ	760
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत बैरागढ़)	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, सीताफल, नींबू, अचार, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1800
कुल			5760

6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय उच्च विद्यालय बैरागढ़ में 5-पंखा, 2-ब्लैक बोर्ड, 40-बेंच की व्यवस्था	60,000
ग्राम बैरागढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2-स्ट्रेचर बेड एवं सामान्य जरूरी चिकित्सीय उपकरण जैसे शुगर, बीपी, वजन नापने की मशीन की व्यवस्था।	40,000
कुल योग	1,00,000

22. Case No 9541/2022 M/s. Euphoria Mines and Minerals, Partner, Shri Himanshu Meena, R/o 9 A, Paramount Villa, Ansals, Shyamla Hills, District-Bhopal (MP)-462013 Prior Environment Clearance for Singrampur River Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (13000 Cum per annum) (Khasra No. 53, 369), Village- Singrampur, Tehsil-Bijawar, District-Chhatarpur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 53, 369), Village- Singrampur, Tehsil-Bijawar, District-Chhatarpur (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की पूर्व बैठक 618 वीं दिनांक 11/01/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु मीणा (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1867 दिनांक 02/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 4.00 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान बन्ने नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-78 के सरल क्रमांक-44 पर इस खदान का विवरण दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-36000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 13,000 m³/year घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। अतः पर्यावरणीय अभिस्वीकृति इसी मात्रा अर्थात् 13,000 घनमीटर/वर्ष हेतु अनुशंसित किया जाये। ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र के पश्चिम दिशा में एक छोटी जल रोकने की संरचना बनी हुई है तथा पूर्व दिशा में भी एक छोटा सा सिविल स्ट्रकचर बना हुआ है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जल रोकने की संरचना के कारण आवंटित खनन क्षेत्र में 250 मीटर को सेटवेक दोनो ओर छोड़ा गया है तथा सिविल स्ट्रकचर के दोनो ओर 50 मीटर का सेटवेक छोड़ा गया है जिस कारण लगभग 0.93 हे. का क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा मात्र 13,000 घन मीटर है (लगभग 54 घन मीटर प्रति दिवस) जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन पूर्वी दिशा से किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे वन विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 13000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 17.40 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 02.83 लाख प्रति वर्ष।

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. परियोजना प्रस्तावक प्रथम वर्ष में ही वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 06.90 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियों चयानित कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे ।
5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति- कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा, डेंचा एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	2200
2	आवांटीत लीज क्षेत्र के आवागमन क्षेत्र में	कटंग बांस, कहवा, खमेर, सफेद, सिरस, नीम, सेमल, आंबला, हरसिंगार, कालासिरस, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ वन विभाग के सुझाव अनुसार	100
2	ग्राम सिंगरामपुरा के ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी, शासकीय विद्यालय में	कदंब, कचनार, पुत्रंजीवा, मौलश्री एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	100
कुल			2400

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम सिंगरामपुरा, के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में रंगाई, पुताई, फर्नीचर(चार नग लकड़ी की कुर्सीयाँ, दस बेंच एवं डेस्क)	60,0000/-

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

सिया की बैठक 769वीं बैठक दिनांक 01/02/2023 परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश-देशांश अनुसार प्रस्तावित खदान के पश्चिम में 01 जल जल रोकने की संरचना एवं पूर्व दिशा में खदान के बीचो-बीच एक सिविल स्ट्रक्चर परिलक्षित हो रहा है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सस्टेनेबल सेंड माईनिंग गाईडलाइन, 2016 तथा इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन फॉर सेंड, 2020 में निर्धारित दूरी छोड़ने के उपरांत न्यूनतम खनन क्षेत्र उपलब्ध होता है, अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया गया है।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 21/02/23 को समिति के समक्ष रखा गया। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया सिया के उपरोक्त तथ्यों को सेक की पूर्व बैठक 618वीं दिनांक 11/01/23 में रिकार्ड करते हुए अनुशंसा की गई है जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा सस्टेनेबल सेंड माईनिंग गाईडलाइन, 2016 तथा इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन फॉर सेंड, 2020 के अनुसार जल रोकने की संरचना एवं एक सिविल स्ट्रक्चर के कारण सेट-बैक प्रस्तावित किया गया था तथा सेट-बैक छोड़ने के पश्चात् लगभग 0.93 हे. क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध पाया गया था। चूंकि आवंटित खदान का कुल क्षेत्र 2.0 हे. (खनन हेतु 0.93 हे.) है अतः न्यूनतम खनन क्षेत्र 01.0 हे. का प्रावधान सेक की पूर्व बैठक 618 वीं दिनांक 11/01/23 में लिये गये निर्णय अनुसार इस स्थिति में लागू नहीं होना चाहिए।

जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों पर चर्चा –

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट आज की बैठक के दौरान प्रस्तुत की गयी। यह प्रकरण एजेण्डा में सूचीबद्ध नहीं था किंतु संबंधित इंदौर जिले से प्राप्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर पूर्व की बैठक में चर्चा हो चुकी है अतः माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता नहीं है तथा जो जानकारी चाही गई है उसके आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।

1 जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट इंदौर –अन्य गौण खनिज रेत को छोड़कर (संशोधित)।

आज दिनांक 26/02/2023 को इंदौर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अवलोकन करने पर समिति ने पाया कि इंदौर जिले की पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से एवं सिया के पत्र क्रमांक 2044 दिनांक 20/02/23 के माध्यम से सेक को प्राप्त हुई है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का परीक्षण करने पर यह पाया कि।

- कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला- इंदौर के पत्र क्र0 1944 दिनांक 02/11/22 (पूर्व प्रेषित पत्र) प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता कि यह DSR जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा अनुमोदित की गई है तथा इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को जिले के पोर्टल पर 21 दिन की अवधि हेतु अपलोड किया गया था एवं निर्धारित अवधि में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए। अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु सेक को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रेषित किया गई।

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 फरवरी 2023

- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक-निरंक के पेज न0. 38-51 में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे दी गई है।
- जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एवं प्रजातियों की जानकारी टेबिल क्रमांक-निरंक के पेज क्र0. 78 से 83 में दे दी गई है।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला- इंदौर के पत्र क्र0 266 दिनांक 03/02/23 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, पौधों की संख्या एवं प्रजाति भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति इंदौर जले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
 - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

- an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
 29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
 33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

- ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

35. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
36. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
37. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
38. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्टिपल जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई -
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

622वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।